भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2570
11 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

आंध्र प्रदेश में ओएनओआरसी योजना

2570. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ख) आंध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
(ग) राज्य में इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा राज्य में इस योजना के लक्षित लाभार्थियों को लाभ मिलना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ) : राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) विशिष्टता के रूप में लोकप्रिय है। प्रौद्योगिकी आधारित इस सुधार के माध्यम से, लगभग 80 करोड़ पीएमजीकेएवाई लाभार्थी ई-पीओएस उपकरण पर बायोमेट्रिक प्रमाणन के साथ अपने उसी मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में किसी भी स्थान पर अपनी पसंद की उचित दर दुकान से अपनी पात्रता के खाद्यान्नों का उठान कर सकते हैं। उनके घर पर निवास करने वाला उनका परिवार भी उसी राशन कार्ड पर उनके गृह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पीएमजीकेएवाई राशन के भाग का उठान कर सकता है।

...2/-

अभी तक, देश के सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में (आंध्र प्रदेश सहित) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) कार्यान्वित कर दी गई है और इसमें लभगग 100% पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को कवर किया गया है। इस विशिष्टता की शुरुआत से, ओएनओआरसी विशिष्टता के अंतर्गत 158 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन (आंध्र प्रदेश सहित 16.12 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन) दर्ज किए गए हैं, जिनमें अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय लेनदेन शामिल हैं।

पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों के लिए ओएनओआरसी एक सार्वभौमिक विशिष्टता है और आंध्र प्रदेश के लिए कोई अलग निधि आबंटित नहीं की गई है।

****